

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 428 का उत्तर

नई रेलवे लाईन परियोजनाएं

428. श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री विजय बघेल:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री मुकेश राजपूत:
श्री आशीष दुबे:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री बलभद्र माझी:
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा नई रेलवे लाइन परियोजनाओं के माध्यम से देश भर के आकांक्षी जिलों विशेष रूप से उड़ीसा के नबरंगपुर, मलकानगिरि, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में

मिसरिख और इसके आस-पास के जिलों और दाहोद में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गये हैं;

- (ख) वर्ष 2014 से 2024 की अवधि के दौरान गुजरात में रेलवे परियोजनाओं से जुड़े आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है तथा इसके लिए बजट में कितनी वृद्धि की गई है;
- (ग) क्या सरकार इन नई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव, विशेष रूप से कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन और तेल आयात को कम करने के लिए, इसकी निगरानी और मूल्यांकन करने की योजना बना रही है जिससे इनके माध्यम से भारत जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त कर सके;
- (घ) विशेष रूप से महाराष्ट्र के पालघर, झारखंड के बड़े शहरों हजारीबाग-रामगढ़ और राजस्थान में नई और चालू रेलवे लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार द्वारा रेलगाड़ियों की वर्तमान गति बढ़ाने के लिए डिवीजन-वार क्या कदम उठाए गये हैं; और
- (च) रेलगाड़ियों के परिचालन में प्रति माह डिवीजन-वार कितनी देर होती है तथा सरकार द्वारा इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

नई रेलवे लाईन परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री तेजस्वी सूर्या, श्री विनोद लखमशी चावड़ा, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री विजय बघेल, श्री विष्णु दयाल राम, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री दिनेशभाई मकवाणा, श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा, श्री मनीष जायसवाल, श्री सुरेश कुमार कश्यप, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री मुकेश राजपूत, श्री आशीष दुबे, श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया, श्री अशोक कुमार रावत और श्री बलभद्र माझी के अतारांकित प्रश्न सं. 428 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क), (ख) एवं (घ): रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत की जाती हैं और इन्हें राज्य-वार/केन्द्रशासित प्रदेश-वार/जिला-वार स्वीकृत नहीं किया जाता है, क्योंकि, रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, देश भर में आकांशापूर्ण जिलों को संपर्कता सहित सामाजिक-आर्थिक आधारों, रणनीतिक महत्व वाले स्थानों, सीमावर्ती क्षेत्रों आदि आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की दायिताओं, निधियों की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों के आधार पर निर्भर करता है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल पर लगभग 4.16 लाख करोड़ रुपये की लागत की 20,199 कि.मी. की कुल लंबाई वाली 187 नई लाइन परियोजनाएं योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिसमें से 2,855 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है, जिस पर मार्च, 2024 तक 1.6 लाख करोड़ रुपये कर व्यय किया गया है।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्र-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

गुजरात

गुजरात राज्य में रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे जोन में आती हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में दाहोद सहित गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले कुल 3,791 कि.मी. लंबाई के 49 सर्वेक्षण (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

दाहोद-इंदौर नई लाइन परियोजना (205 कि.मी.) का 32 कि.मी. खंड कमीशन कर दिया गया है और 31.03.2024 तक इस पर 1587 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। शेष खंड में कार्य आरंभ कर दिया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 30,826 करोड़ रुपये लागत की 2948 कि.मी. कुल लंबाई वाली 42 परियोजनाएं (06 नई लाइन, 22 आमान परिवर्तन और 14 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिसमें से 825 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 9,335 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	589 करोड़ रुपये/वर्ष	-
2024-25	8,743 करोड़ रुपये	लगभग 14.84 गुना

वर्ष 2009-14 और 2014-2024 के दौरान गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) को कमीशन करने का ब्यौरा इस प्रकार है:

अवधि	कुल कमीशन	औसत कमीशन	2009-14 के औसत कमीशन की तुलना में वृद्धि
2009-14	660 कि.मी	132 कि.मी./वर्ष	-
2014-24	2,244 कि.मी.	224 कि.मी./वर्ष	1.69 गुना

गुजरात में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 567 कि.मी. खंड को कमीशन किया गया है।

राजस्थान

राजस्थान राज्य में रेल परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर पश्चिम रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे जोन में आती हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले कुल 4,944 कि.मी. कुल लंबाई वाले 55 (नई लाइन और दोहरीकरण) सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं।

01.04.2024 को राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 51,814 करोड़ रुपये लागत की 4,191 कि.मी. कुल लंबाई वाली 32 परियोजनाएं (15 नई लाइनें, 5 आमान परिवर्तन और 12 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिसमें से 1,183 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और इस पर मार्च, 2024 तक 14,786 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	682 करोड़ रुपये/वर्ष	-
2024-25	9,959 करोड़ रुपये	लगभग 14.6 गुना

वर्ष 2009-14 और 2014-2024 के दौरान राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) को कमीशन करने का ब्यौरा इस प्रकार है:

अवधि	कुल कमीशन	औसत कमीशन	2009-14 के औसत कमीशन की तुलना में वृद्धि
2009-14	798 कि.मी.	159.6 कि.मी./वर्ष	-
2014-24	3,742 कि.मी.	374.2 कि.मी./वर्ष	लगभग 2.34 गुना

झारखंड

झारखंड राज्य की रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में आती हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में हजारीबाग-रामगढ़ सहित झारखंड राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले 3,323 कि.मी. कुल लंबाई वाले 84 सर्वेक्षण (नई लाइन और दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

01.04.2024 को झारखंड राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 52,885 करोड़ रुपये लागत की 3,070 कि.मी. कुल लंबाई वाली 32 परियोजनाएं (11 नई लाइनें, 01 आमान परिवर्तन और 20 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिसमें से 744 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक इस पर 15,986 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

झारखंड राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	457 करोड़ रुपये/वर्ष	-
2024-25	7,302 करोड़ रुपये	लगभग 15.98 गुना

वर्ष 2009-14 और 2014-2024 के दौरान झारखंड राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) को कमीशन करने का ब्यौरा इस प्रकार है:

अवधि	कुल कमीशन	औसत कमीशन	2009-14 के औसत कमीशन की तुलना में वृद्धि
2009-14	287 कि.मी.	57.4 कि.मी./वर्ष	-
2014-24	1,218 कि.मी.	121.8 कि.मी./वर्ष	लगभग 2.12 गुना

झारखंड में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 124 कि.मी. खंड को कमीशन किया गया है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भारतीय रेल के मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, और पश्चिम रेलवे जोन में आती हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में पालघर सहित महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले 7,458 कि.मी. कुल लंबाई वाले 91 अदद (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) सर्वेक्षण स्वीकृत किए गए हैं।

01.04.2024 को महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 81,580 करोड़ रुपये लागत की 5,877 कि.मी. कुल लंबाई की 41 परियोजनाएं (16 नई लाइनें, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिसमें से 1,926 कि.मी. लंबी रेल लाइन को कमीशन कर दिया गया है और इस पर मार्च, 2024 तक 31,236 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	1171 करोड़ रुपये/वर्ष	-
2024-24	15940 करोड़ रुपये/वर्ष	लगभग 13.61 गुना

वर्ष 2009-14 और 2014-2024 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) को कमीशन करने का ब्यौरा इस प्रकार है:

अवधि	कुल कमीशनिंग	औसत कमीशनिंग	2009-14 के औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	292 कि.मी.	58.4 कि.मी./वर्ष	-
2014-24	1830 कि.मी.	183 कि.मी./वर्ष	लगभग 3 गुना

महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 358 कि.मी. खंड को कमीशन किया गया है।

ओडिशा

ओडिशा राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्वतट रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में आती हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में मलकानगिरी, नबरंगपुर सहित ओडिशा राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले 5,598 कि.मी. कुल लंबाई वाले 90 अदद सर्वेक्षण (नई लाइन और दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

01.04.2024 को ओडिशा राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 54,434 करोड़ रुपये लागत की 4,017 कि.मी. कुल लंबाई की 40 परियोजनाएं (13 नई लाइनें, 1 आमान परिवर्तन और 26 दोहरीकरण) हैं, जो योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिसमें से 1,100 कि.मी. लंबी रेल

लाइन को कमीशन कर दिया गया है और इस पर मार्च, 2024 तक 22,833 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

हाल ही में ओडिशा राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली निम्नलिखित नई रेल लाइन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:

पुरी-कोणार्क (32.02 कि.मी.), गुनुपुर-थेरुबली (73.62 कि.मी.), मलकानगिरि-पांडुरंगपुरम बरास्ता भद्राचलम (173.61 कि.मी.), बदामपाहाड़-केंदुझरगड़ (82.06 कि.मी.), जूनागढ़-नबरंगपुर (116.21 कि.मी.), बुढ़ामरा-चाकुलिया (59.96 कि.मी.), बंग्रिपोसी-गोरुमाहिसानी (85.6 कि.मी.), बरगद रोड-नुआपड़ा रोड (138.32 कि.मी.), सारडेगा-भालुमुड़ा (37.24 कि.मी.)।

ओडिशा राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	बजट परिव्यय	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	838 करोड़ रुपये/वर्ष	-
2024-25	10,586 करोड़ रुपये	12.6 गुना

वर्ष 2009-14 और 2014-2024 के दौरान ओडिशा राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) को कमीशन करने का ब्यौरा इस प्रकार है:

अवधि	कुल कमीशन की गई लंबाई	प्रतिवर्ष कमीशनिंग	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में कमीशनिंग में वृद्धि
2009-14	267 कि.मी.	53.4 कि.मी.	-
2014-24	1827 कि.मी.	182.7 कि.मी.	लगभग 3.5 गुना

ओडिशा में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 243 कि.मी. खंड को कमीशन किया गया है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाली रेल परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आती हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में मिसरिख सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले 5,310 कि.मी. कुल लंबाई वाले 92 अदद सर्वेक्षण (नई लाइन और दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

01.04.2024 को उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 92,001 करोड़ रुपये लागत की 5,874 कि.मी. कुल लंबाई वाली 68 रेल परियोजनाएं (16 नई लाइनें, 03 आमान परिवर्तन और 49 दोहरीकरण) योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें से 1,313 कि.मी. लंबी रेल लाइन को कमीशन कर दिया गया है और इस पर मार्च, 2024 तक 28,366 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	1,109 करोड़ रुपये/वर्ष	-
2024-25	19,848 करोड़ रुपये/वर्ष	17.89 गुना

वर्ष 2009-14 और 2014-2024 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) को कमीशन करने का ब्यौरा इस प्रकार है:

अवधि	कुल कमीशन किए गए रेलपथ	औसत कमीशन रेलपथ	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	996 कि.मी.	199.2 कि.मी./वर्ष	-
2014-24	4,902 कि.मी.	490.2 कि.मी./वर्ष	2.46 गुना

उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1,752 कि.मी. खंडों को कमीशन किया गया है।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ने वाली रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भारतीय रेल के उत्तर रेलवे जोन में आती हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 441 कि.मी. कुल लंबाई वाले 05 अदद सर्वेक्षण (नई लाइन और आमान परिवर्तन) स्वीकृत किए गए हैं।

01.04.2024 को हिमाचल प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः 13,168 करोड़ रुपये लागत की 255 कि.मी. कुल लंबाई वाली 04 नई लाइन परियोजनाएं योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरण में हैं, जिसमें से 61 कि.मी. लंबी रेल लाइन को कमीशन कर दिया गया है और इस पर मार्च, 2024 तक 6,225 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	108 करोड़ रुपये/वर्ष	-
2024-25	2,698 करोड़ रुपये	लगभग 25 गुना

(ग): रेलवे अत्यंत पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है। रेल द्वारा परिवहन की लागत सड़क द्वारा परिवहन की लागत की तुलना में आधी से भी कम है। रेल नेटवर्क का विस्तार और क्षमता संवर्धन परियोजनाएं जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति और परिवहन की लॉजिस्टिक लागत को कम करने में योगदान देते हैं। कई अध्ययनों में यह सिद्ध हुआ है कि रेल परिवहन द्वारा सीओ₂ उत्सर्जन सड़क द्वारा परिवहन की तुलना में कई गुना कम है। अतः इस प्रकार रेल नेटवर्क का विस्तार देश के कार्बन फुटप्रिंटों को कम करने में निरपवाद रूप से सहायता करता है।

भारतीय रेल का फोकस जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाते हुए तेल आयात को कम करने पर है। इस प्रयास में, अक्टूबर 2024 तक भारतीय रेल पर लगभग 366 मेगावाट सौर संयंत्रों (छत और जमीन दोनों) और लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र कमीशन किए गए हैं।

(ड) से (च): यात्री ले जाने वाली गाड़ियों की औसत गति कोचिंग स्टॉक की किस्म, उपयोग किया गया कर्षण, अधिकतम अनुमेय गति, गति प्रतिबंधों, ग्रेडियंट और ढालों, खंडों का लाइन क्षमता उपयोगिता और मार्ग में ठहराव जैसे कारकों पर निर्भर करता है। गाड़ी सेवाओं में तेजी लाने के अपने निरंतर प्रयास में, भारतीय रेल वंदे भारत, अमृत भारत, नमो रैपिड रेल सेवाओं आदि की शुरुआत करते हुए एलएचबी कोचों की संख्या बढ़ा कोचिंग स्टॉक को अपग्रेड कर रही है। गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न मार्गों की पहचान की जाती है और तदनुसार शुरु की जाती है। गति को 130 किमी तक बढ़ाना एक निरंतर और सतत् प्रक्रिया है। अब तक, भारतीय रेल में लगभग 11,000 मार्ग किलोमीटर पर खंडीय गति

को 130 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ गाड़ियों को गति बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रेल ने 2020-21 के दौरान आईआईटी-मुंबई की सहायता से वैज्ञानिक तरीके से समय-सारिणी को यौक्तपूर्ण बनाने का काम भी किया है।

भारतीय रेल, गाड़ियों को उनके समय-अनुसूची के अनुसार और समय पर चलाने के लिए सभी प्रयास करती है। बहरहाल, कभी-कभी, आपातकालीन सुरक्षा संबंधी कार्य, प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन, खराब मौसम, दुर्घटनाएं, कानून और व्यवस्था की समस्याएं आदि जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में गाड़ियां चलने में विलंब हो जाता है। गाड़ियों के समयपालन को प्रभावित करने वाली विफलताओं के संबंध में मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर दैनिक आधार पर मूल कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है और विश्लेषण के आधार पर, तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। अप्रैल-24 से अक्टूबर-2024 के दौरान, भारतीय रेल के सभी मंडलों की मेल/एक्सप्रेस गाड़ी सेवाओं का औसत समयपालन लगभग 79% है।
